



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 मार्च, 2005/9 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला, 30 मार्च, 2005

संख्या एच०पी०इ०आर०सी०/414.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (फ) तथा (ब) के साथ पठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश विद्युत

4128-राजपत्र/2005-30-3-2005—1,624. (4369) मूल्य : एक रुपया।

विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के उपरान्त, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2005 है।

(2) ये विनियम हिमाचल प्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को, उनके अनुज्ञप्त क्षेत्रों में लागू होंगे।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन विनियमनों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
- (ख) "आवेदक" से परसिर का स्वामी या अधिभोगी, जो विद्युत प्रदाय के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करता है, अभिप्रेत है;
- (ग) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) "उपभोग प्रभार" से kWh/kVAh के हिसाब से विद्युत उर्जा के उपभोग से समुचित टैरिफ रेट के गुणित अभिप्रेत है और इसमें, जहाँ कहीं लागू हो, माँग प्रभार/नियत प्रभार तथा ग्राहक प्रभार इत्यादि, भी आते हैं;
- (ङ) "अनुज्ञप्तिधारी" से अपने प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को किसी भी बोल्टा पर विद्युत प्रदाय करने के लिए वितरण प्रणाली को प्रचालित करने और उसका रख-रखाव करने के लिए प्राधिकृत वितरण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;
- (च) "मास" से कलेंडर मास अभिप्रेत है तथा बिलों के प्रयोजन के लिए दो क्रमवर्ती मीटर रीडिंग में आने वाली लगभग 30 दिन की अवधि भी एक मास समझी जायेगी;
- (छ) "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई कम्पनी या निगम, निकाय या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति आता है, और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, विभाग, राज्य सरकारी उपक्रम तथा उनके कर्मचारी भी आते हैं;
- (ज) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ; तथा

(झ) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु यहाँ परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उन के लिए अधिनियम में नियत किए गए हैं ।

3. प्रतिभूति की अपेक्षा करने की शक्ति.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विनियम 4 में यथाउपबन्धित, प्रत्येक व्यक्ति से, जो धारा 43 के अनुसरण में अपने परिसर को विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करता है, उसे प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा जो ऐसे सभी धन के, जो निम्नलिखित के लिए उसको देय हो जाएँ, संदाय के लिए :—

- (क) ऐसे व्यक्ति को प्रदाय की गई विद्युत की बावत हो; या
- (ख) जहां कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर ऐसे व्यक्ति को प्रदाय के लिए उपलब्ध कराया जाना है, वहाँ ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर की बाबत हो ।

(2) यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि ठीक समझे, उस अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, विद्युत का प्रदाय करने से या लाइन या संयंत्र या मीटर उपलब्ध करने से इन्कार कर सकेगा ।

4. विद्युत प्रदाय के लिए प्रतिभूति निक्षेप.— (1) उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के करार की अवधि के दौरान, उपभोक्ता, हर समय, अनुज्ञप्तिधारी के पास, बिलिंग चक्कर अवधि के उपभोग प्रभार के बराबर प्रतिभूति रखेगा :

परन्तु यह कि यदि बिलिंग व्यवस्था बदली जाती है, तो प्रतिभूति निक्षेप यथानुपात घटाया/बढ़ाया जाएगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति पूर्व संदाय मीटर के माध्यम से विद्युत लेने को तैयार है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे व्यक्ति से प्रदाय की गई विद्युत की बावत प्रतिभूति निक्षेप लेने का अधिकार नहीं होगा :

परन्तु यह कि उस दशा में जब विद्यमान उपभोक्ता पूर्वसंदाय मीटर के माध्यम से विद्युत लेने का विकल्प करता है, तब वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अपने पास रखी हुई प्रतिभूति निक्षेप की राशि लौटायेगा ।

(3) देय प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप का संदाय विनियम 5 में उल्लिखित सपाट दरों पर विद्युत प्रदाय करते समय किया जाएगा ।

(4) प्रतिभूति नकद अथवा अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में देय माँगदेय ड्राफ्ट के रूप में दी जाएगी:

परन्तु यह कि उस दशा में जब प्रतिभूति निक्षेप की देय राशि 5 लाख रुपए से अधिक हो, तब उपभोक्ता को विकल्प होगा कि वह प्रतिभूति निक्षेप बैंक गारन्टी के रूप में दे ।

5. प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप.— (1) आवेदक उसे प्रदाय की जाने वाली विद्युत के लिए, निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित सपाट दरों पर प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप सदंत करेगा :—

सारणी

क्रम संख्या	प्रवर्ग स्वरूप	संयोजित भार/संवेदित मांग के प्रति किलो वाट/कै.वी.ए. अथवा उसके भाग की दर पर प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप (राशि रुपयों में)			
		चतुर्मासिक बिलिंग	त्रैमासिक बिलिंग	द्विमासिक बिलिंग	मासिक बिलिंग
1.	जनजातीय, दूरस्थ, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में मीटर के माध्यम से अस्थायी प्रदाय तथा मार्ग प्रकाश हेतु प्रदाय के सिवाय 20 किलोवाट तक के सभी प्रवर्गों के लिए।	330	—	—	—
2.	जनजातीय दूरस्थ, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों, प्रपुंज प्रदाय, मीटर के माध्यम से अस्थायी प्रदाय तथा मार्ग प्रकाश हेतु प्रदाय के सिवाय, सभी प्रवर्गों के लिए 20 किलोवाट से अधिक पर।	—	—	240	—
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्योगों, मीटर के माध्यम से अस्थायी प्रदाय तथा मार्ग प्रकाश हेतु प्रदाय के सिवाय, सभी प्रवर्गों के लिए 20 किलोवाट तक।	—	360	—	—
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में, उद्योगों, प्रपुंज प्रदाय, मीटर के माध्यम से अस्थायी प्रदाय तथा मार्ग प्रकाश हेतु प्रदाय के सिवाय, सभी प्रवर्गों के लिए 20 किलोवाट से अधिक पर।	—	—	—	120
5.	औद्योगिक प्रदाय प्रपुंज विद्युत प्रदाय, मीटर के माध्यम से अस्थायी प्रदाय तथा मार्ग प्रकाश के सिवाय, शहरी क्षेत्रों में 20 किलो वाट तक—				
(क)	घरेलू प्रदाय हेतु :	—	—	340	—
(ख)	वाणिज्यिक प्रदाय/गैर घरेलू/गैर वाणिज्यिक/जल पम्पिंग प्रदाय हेतु —	—	—	700	—
6.	औद्योगिक प्रदाय; प्रपुंज प्रदाय मीटर के माध्यम से				

1	2	3	4	5	6
	अस्थायी प्रदाय तथा मार्ग प्रकाश के सिवाय शहरी क्षेत्रों में 20 किलोवाट से अधिक :				
(क)	घरेलू प्रदाय हेतु :	---	---	---	170
(ख)	वाणिज्यिक प्रदाय/गैर घरेलू/गैर वाणिज्यिक/जल पम्पिंग प्रदाय हेतु -	---	---	---	350
	उद्योग, प्रपुंज, विद्युत प्रदाय, मीटर के माध्यम से अस्थायी प्रदाय तथा मार्ग प्रकाश				
7.	जनजातीय, दूरस्थ, कठिन एवं दूरगम क्षेत्रों के सिवाय सभी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए विद्युत प्रदाय के लिए 20 किलोवाट तक -	---	---	---	500
8.	सभी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए (20 किलोवाट से 100 किलोवाट तक)के विद्युत प्रदाय के लिए-	---	---	---	750
9.	सभी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के लिए विद्युत प्रदाय के लिए-100 किलोवाट से अधिक विद्युत प्रदाय के लिए-	---	---	---	1000
10.	सभी क्षेत्रों में प्रपुंज विद्युत प्रदाय के लिए	---	---	---	850
11.	सभी क्षेत्रों में मीटर के माध्यम से अस्थायी विद्युत प्रदाय के लिए।	---	---	---	850
12.	सभी क्षेत्रों में मार्ग प्रकाश हेतु 20 किलोवाट से अधिक के लिए।	---	---	---	500

स्पष्टीकरण - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "दूरस्थ, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्र" से अभिप्रेत वे क्षेत्र हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दूरस्थ, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्र घोषित किए जाएँ ;
- (ख) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत वे क्षेत्र हैं जो शहरी क्षेत्र नहीं हैं ;
- (ग) "जनजातीय क्षेत्र" से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो भारतीय संविधान की अनुसूची-V के भाग (ग) के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएँ ;
- (घ) "शहरी क्षेत्र" से वे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो नगरपालिकाओं से सम्बन्धित अधिनियम के अधीन बड़े शहरी क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्र अथवा परिवर्ती शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए हैं;

(2) केवल उस उपभोक्ता, जिसे अतिरिक्त मांग मन्जूर की गई है, के मामले में ही अतिरिक्त मांग के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप ।

(3) यदि आवेदक इस विनियम के निबंधनों के अनुसार प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप का संदाय नहीं करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय करने से इन्कार कर सकता है ।

6. पुनर्विलोकन तथा विद्युत प्रदाय के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान:—

(1) साधारण पुनर्विलोकन .— विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट बिलिंग अवधि के अध्यक्षीन रहते हुए, विनियम 9 के अधीन पुअर (poor) प्रतययमापित उपभोक्ताओं की प्रतिभूति निक्षेप की रकम की अपर्याप्ता अनुज्ञप्तिधारी, साधारणतयः प्रतिवर्ष एक बार (अधिमान्यतः सम्बन्धित वर्ष के टैरिफ के संशोधन के उपरान्त) पूर्व वर्ष के 12 (बारह) महीनों की अवधि, अप्रैल से मार्च तक, के औस्त उपभोग के आधार पर, पुनर्विलोकित करेगा ।

(2) अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप के लिखे माँग सूचना,—

(क) अनुज्ञप्तिधारी, उप-विनियम (1) के पुनर्विलोकन पर आधारित कमी पूरा करने की माँग करेगा:

परन्तु यह कि यदि उक्त कमी विद्यमान प्रतिभूति निक्षेप के 10 प्रतिशत से अनधिक होती है तो अनुज्ञप्तिधारी माँग नहीं करेगा ।

(ख) जहाँ उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप अपेक्षित है वहाँ अनुज्ञप्तिधारी देय राशि का उल्लेख करते हुए समर्थक परिकलन सहित उपभोक्ता को 30 दिन की माँग सूचना भेजेगा ।

(3) अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप के विलम्बित भुगतान पर अधिभार,—

(क) उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भेजी गई माँग सूचना की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगा ।

(ख) यदि भुगतान में विलम्ब होता है, तो उपभोक्ता, इस विनियम के उप-विनियम (4) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत काटने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से या ऐसी दरों से जैसी आयोग द्वारा समय समय पर नियत की जाएं, साधारण ब्याज संदत करेगा ।

(4) प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान न करने पर विद्युत काटना.— जहां इस विनियम के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की माँग की जाती है और उपभोक्ता भुगतान नहीं करता है, तो उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय, बिना और कोई सूचना के, काटा जा सकेगा ।

7. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज.— (1) अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (2) के अन्वये रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति निक्षेप पर उपभोक्ता को उस तारीख, जिसको प्रतिभूति निक्षेप जमा किया जाता है, के उत्तरवर्ती मास से प्रथम अप्रैल को लागू बैंक दर, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की गई है, या ऐसी उच्च दर, जो आयोग द्वारा समय-समय पर, नियत की जाए, पर ब्याज का भुगतान करेगा और देय ब्याज की रकम निकटतम रुपये तक पूर्णांकित की जाएगी ।

(2) यदि प्रतिभूति निक्षेप की रकम 100 रुपये से कम होती है या विद्युत प्रदाय करने से एक वर्ष से पहले विद्युत काट दी जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून को उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय बकाया राशि अथवा उसके तत्पश्चात् उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय होने वाली बकाया राशि में प्रतिवर्ष उपभोक्ता को संदेय होने वाला ब्याज समायोजित किया जाएगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को दिये जाने वाले बिलों में, जो 30 जून के पश्चात् देय हों, उपभोक्ता को प्रतिभूति निक्षेप पर देय ब्याज राशि का उल्लेख करेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति निक्षेप पर उपभोक्ताओं को प्रोदभूत ब्याज का खाता अलग लेखा शीर्ष में रखेगा ।

(6) प्रतिभूति निक्षेप पर प्रोदभूत ब्याज का उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से 30 दिनों की कालावधि के पश्चात् भी समायोजन में विलम्ब करने पर, अनुज्ञप्तिधारी देय ब्याज पर उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर से दुगुनी दर पर शास्तिक ब्याज संदत्त करेगा । अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं में यह शास्तिक ब्याज उपभोक्ताओं को पास थू (pass through) नहीं होगा ।

8. प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय.— (1) जहां विद्युत प्रदाय के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार किसी विद्युत प्रदाय के करार को खत्म कर दिया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति निक्षेप का, यदि कोई हो, उपभोक्ता द्वारा उसे देय बकाया राशि को समायोजित करने के उपरान्त, करार के खत्म करने की तारीख से 10 दिन के भीतर, प्रतिदाय करना होगा :

परन्तु यह कि यदि यथाउपरिनिर्दिष्ट के अनुसार प्रतिप्रदाय करने में एक मास से अधिक विलम्ब हो जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करार खत्म करने की तारीख से उक्त निक्षेप पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज देगा ।

(2) जहां उपभोक्ता संवेदित माँग/संयोजित भार को घटाता है या बिल चक्कर घटाया जाता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी यथानुपात के आधार पर प्रतिभूति निक्षेप घटाएगा और अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता को देय बकाया को समायोजित करने के उपरान्त, अनुज्ञप्तिधारी अधिक राशि को, संवेदित माँग/संयोजित भार में कमी की प्रभावी तारीख से एक मास के भीतर, लौटाएगा :

परन्तु यह कि यदि एक मास की कालावधि में प्रतिदाय नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संवेदित माँग/संयोजित भार के घटाने की प्रभावी तारीख से, 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज देगा ।

प्रकीर्ण

9. प्रत्ययमाप.—(1) प्रतिवर्ष अनुज्ञप्तिधारी नामवार परामर्शियों के माध्यम से उपभोक्ताओं का प्रत्ययमापन कराएगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, प्रतिवर्ष उन पुअर (poor) प्रत्ययमापित उपभोक्ताओं की, जो दस हजार रुपये से अधिक की रकम के अभ्यस्त व्यक्तिकमी हों, सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और उसको वेबसाईट पर दिखाएगा ।

10. कठिनाईयाँ दूर करना.— यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग, स्वप्रेरणा अथवा आवेदन पर, ऐसा कुछ भी कर सकता है अथवा साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी समुचित कारवाई, जो अधिनियम से असंगत न हो, करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, जो आयोग को ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

11. आदेश और कार्य—पद्धति—निदेश जारी करना.— आयोग इस अधिनियम और इन विनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, समय समय पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और आनुषांगिक तथा प्रासंगिक मामलों के सम्बन्ध में, आदेश और कार्य—पद्धति निदेश जारी कर सकता है ।

12. निर्वचन.— इन विनियमों के सम्बन्ध में उद्भूत सभी विवादक, आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे तथा उन विवादकों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

आयोग के आदेश द्वारा

हस्ता10/—

सचिव।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 30th March, 2005

F.No.HPERC/414.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by clauses (v) and (w) of sub-section (2), of section 181 read with section 47 of the Electricity Act, 2003(36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely :—

REGULATIONS

1. Short title, extent and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall be applicable to all distribution licensees in their respective licensed areas, in the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) ;

(b) “applicant” means the owner or occupier of any premises who makes an application to the distribution licensee for supply of electricity ;

(c) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;

(d) “consumption charges” means the consumption of electrical energy in kWh or kVAh multiplied by appropriate tariff rates and also includes demand/fixed charges, and customer charges etc., wherever applicable ;

(e) “licensee” means a distribution licensee authorized to operate and maintain a distribution system and supply electricity at any voltage to consumers in the concerned area of supply ;

- (f) "month" means the calendar month and the period of about 30 days between the two consecutive meter readings shall also be regarded as a month for the purpose of billing ;
- (g) "person" shall include any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person and also includes the Central and the State Government Department, the State Government Undertaking and their employees;
- (h) "State" means the State of Himachal Pradesh; and
- (i) other words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. Power to require security.— (1) The distribution licensee shall require every person, who requires a supply of electricity to his premises in pursuance of section 43 of the Act, to give security as provided in regulation 4, for the payment of all monies, which may become due to the licensee —

- (a) in respect of the electricity supplied to such person ; or/and
- (b) where any electric line or electrical plant or electric meter is to be provided for supplying electricity to such person, in respect of the provision of such line, plant and/or meter.

(2) If such person fails to give such security under sub-regulation (1), the distribution licensee may refuse to give the supply of electricity or to provide the line or plant or meter for the period during which the failure continues.

4. Security deposit for the supply of electricity.— (1) The consumer shall, at all times maintain with the licensee an amount equivalent to consumption charges for the billing cycle period, as security during the period the agreement for supply of energy to such consumer remains in force :

Provided that where billing cycle is changed the security deposit shall be reduced/increased on *pro-rata* basis.

(2) If any person is prepared to take the supply through a pre-payment meter, the distribution licensee shall not be entitled to collect the security deposit in respect of the electricity supplied to such person:

Provided that in the case of existing consumer who opts for the supply through the pre-payment meter, the licensee shall refund the amount of the security deposit of such consumer lying with the licensee.

(3) The initial security deposit payable at the time of releasing the supply shall be at flat rates mentioned in regulation 5.

(4) The amount payable towards security shall be in the form of cash/demand draft (DD) drawn in favour of the licensee:

Provided that where the amount payable towards security exceeds rupees 5.00 lacs, the consumer may opt to furnish the security in the form of Bank Guarantee.

5. **Initial security deposit.** — (1) The applicant shall pay initial security deposit towards the electricity to be supplied to him at the flat rates as given in the following table :—

Table

Sl. No.	Type of category	Initial security deposit per kW/kVA or fraction thereof of connected load/contract demand (amount in rupees)			
		4 months billing	3 months billing	2 months billing	monthly billing
1	2	3	4	5	6
1.	Tribal areas, remote, difficult and hard areas - all categories except temporary metered supply and street light supply upto 20 kW.	330	—	—	—
2.	Tribal areas, remote, difficult and hard areas-all categories above 20 kW except industry, bulk supply, temporary metered supply and street light supply.	—	—	240	—
3.	Rural areas all categories upto 20 kW, except industries, temporary metered supply and street light supply.	—	360	—	—
4.	Rural areas all categories above 20 kW, except industries and bulk supply, temporary metered supply and street light supply.	—	—	—	120
5.	Urban areas up to 20 kW except industries, bulk supply, temporary metered supply and street supply				
	(a) DS	—	—	340	—
	(b) CS/NDNCS/WPS	—	—	700	—
6.	Urban areas above 20 kW except industries, bulk supply, temporary metered supply and street supply				
	(a) DS	—	—	—	170

1	2	3	4	5	6
	(b) CS/NDNCS/WPS Industries bulk supply, temporary metered supply and street light supply.	—	—	—	350
7.	Small and medium industries power supply upto 20 KW for all areas except tribal, remote, difficult and hard areas.	—	—	—	500
8.	Small and medium industrial power supply (Above 20 kW to 100 kW) for all areas.	—	—	—	750
9.	Large industries power supply (above 100 kW) for all areas.	—	—	—	1000
10.	Bulk supply (BS) for all areas	—	—	—	850
11.	Temporary metered supply for all areas	—	—	—	850
12.	Street light supply above 20 kW for all areas	—	—	—	500

Explanation.—For the purpose of this regulation,—

- (a) “remote, difficult and hard areas” means the areas which are declared as remote, difficult and hard areas by the State Government from time to time.
- (b) “rural areas” means the areas which are not the urban areas.
- (c) “tribal areas” means such areas as may by order be declared to be Scheduled Areas under Part-C of the Fifth Schedule to the Constitution of India.
- (d) “urban areas” means the areas which are declared as the larger urban areas, the smaller urban areas or the transitional urban areas under the Act concerning the municipalities.

(2) In the case of consumers who have sanctioned additional demand, the additional security deposit shall be calculated only for the additional demand.

(3) If the applicant does not make payment of initial security deposit in terms of this regulation, the licensee can refuse to release supply.

6. Review and payment of additional security deposit for the electricity supplied.—(1) **General review.**— Subject to the billing periods as specified in regulation 4, the adequacy of the amount of security deposit in respect of the consumers credit-rated as poor under regulation 9, shall be reviewed by the licensee generally once in every year (preferably after revision of tariff for the respective year) based on the average consumption for the period representing 12 (twelve) months from April to March of the previous year.

(2) **Demand notice for additional security deposit.**—

- (a) Based on the review as per sub-regulation (1), the demand for shortfall will be made by the licensee :

Provided that if the short fall is less than 10% of the existing security deposit, no demand shall be made by the licensee.

- (b) Where the consumer is required to pay additional security deposit, the licensee shall issue, to the consumer, a 30 days' demand notice specifying the amount payable with supporting calculations.

(3) Surcharge for belated payment of additional security deposit.—

- (a) The consumer shall pay the additional security deposit within thirty days from the date of service of the demand notice issued by the licensee.

- (b) If there is any delay in payment, the consumer shall pay simple interest thereon at 12% per annum or at such rates as may be fixed by the Commission from time to time, without prejudice to the licensee's right to disconnect supply of electricity, as per sub-regulation (4) of this regulation.

(4) Disconnection for non-payment of additional security deposit for the electricity supplied.— Where additional security deposit is demanded by the licensee in terms of this regulation, and the consumer does not make the payment, the supply to the consumer shall be liable for disconnection, without any further notice.

7. Interest on security deposit payable by the licensee.— (1) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 47 of the Act, the licensee shall, with effect from the month succeeding the date on which the security amount is deposited, pay simple interest on security deposit of the consumer at the Bank Rate (as on 1st April of every year) as notified by the Reserve Bank of India or such higher rate as may be fixed by the Commission from time to time and the amount of interest payable shall be rounded off to the nearest rupee.

(2) Where either the security deposit is less than rupees 100 or a connection is disconnected within one year after giving the supply, no interest shall be payable thereon.

(3) The interest accruing to the credit of the consumer shall be adjusted annually against the amounts outstanding from the consumer to the licensee as on 30th June of every financial year and the amounts becoming due from the consumer to the licensee immediately thereafter.

(4) The licensee shall duly show the amounts becoming due to the consumer towards interest on the security deposit in the bills raised on the consumer and due after 30th June.

(5) The distribution licensee shall maintain for accrual of interest on security deposit of the consumers a separate head of account.

(6) The licensee shall pay penal interest on the interest payable at twice the rate specified under sub-regulation (1) for the delay in making the adjustments for interest on security deposit beyond a period of 30 days after the date as specified in sub-regulation (3). This penal interest shall not be a pass through to the consumers in the licensee's Annual Revenue Requirement.

8. Refund of security deposit.— (1) Where an agreement for supply of electricity

is terminated as per the terms and conditions of supply, the licensee shall be required to refund the security deposit if any, after making adjustments for the amounts outstanding from the consumer to the licensee, within one month of the effective date of termination of the agreement :

Provided that if such refund is delayed beyond the period of one month as specified above, the licensee shall pay simple interest on such deposit @ 12 % per annum from the effective date of termination of the agreement without prejudice to other rights of and remedies available to the consumer.

(2) Where contract demand/connected load is reduced by the consumer or the billing cycle is reduced, the licensee shall reduce the amount of security on *pro-rata* basis and refund excess amount, after making adjustments for the amounts outstanding from the consumer to the licensee, within one month of the effective date of reduction of contract demand/connected load:

Provided that if such refund is delayed beyond the period of one month as specified above, the licensee shall pay simple interest on such deposit @ 12 % per annum from the effective date of reduction of contract demand/connected load, without prejudice to other rights of and remedies available to the consumer.

Miscellaneous

9. **Credit Rating.**—(1) Every year, the licensee shall, through reputed consultants, carry out the credit rating of the existing consumers.

(2) Every year the licensee shall publish the list of poorly rated consumers who are habitually defaulters for an amount exceeding rupees ten thousand in the newspapers and host the same on its website.

10. **Power to remove difficulties.**— (1) In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, either *suo motu* or on application made to it, do or undertake to do things, or by general or special order direct the licensee to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

11. **Issue of orders and practice directions.**— Subject to the provisions of the Act, and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and procedures to be followed for such implementation and matters incidental or ancillary thereto.

12. **Interpretation.**— All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

By order of the Commission,

Sd/-

Secretary.